ALL INDIA FORUM AGAINST PRIVATISATION (AIFAP)

AN ATTACK ON ONE IS AN ATTACK ON ALL!

Website: https://aifap.org.in
Email: contact@aifap.org.in

WhatsApp Number:
+918454018757

प्रति
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस,

सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फ़ोरम आपके न्यायसंगत संघर्ष का तहे दिल से समर्थन करता है, जो प्रस्तावित विधेयक के खिलाफ है जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र की दो बैंको के निजीकरण को संभव बनाएगा और बाद में अधिकांश बैंकों के निजीकरण को भी। हम 16 और 17 दिसंबर 2021 को आपकी प्रस्तावित अखिल भारतीय हड़ताल और उससे पहले विभिन्न विरोध कार्रवाइयों की पूर्ण सफलता कामना करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण एक मजदूर विरोधी, जनविरोधी और समाज विरोधी कदम है।

बार-बार, हम श्रमिकों ने पाया है कि सार्वजनिक उपक्रम के निजीकरण के कारण सैकड़ों मजदूरों को नौकरी से निकाला जा रहा है। निजीकरण के कारण ही लगातार ठेका श्रमिकों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, जो स्थायी श्रमिकों के एक-तिहाई या एक-चौथाई वेतन पर काम करते हैं। निजीकरण के बाद, स्थायी और ठेका दोनों श्रमिकों को बिना ओवरटाइम के लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। मौजूदा यूनियनों को नए पूंजीवादी मालिकों द्वारा तोड़ा जा रहा है और नए श्रमिकों को संगठित होने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार निजीकरण का मजदूर विरोधी कदम पूरे मज़दूर वर्ग को कमज़ोर करता है।

देश में लोगों के लिए बैंकों में जमा बचत की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। निजी बैंकों जैसे इंडसइंड बैंक, पीएमसी बैंक आदि के साथ हाल की समस्याओं ने केवल लाभ कमाने के लिए काम कर रही निजी बैंकों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की दो बड़ी बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव पूरी तरह से लोगों के हितों के खिलाफ है।

निजीकरण समाज विरोधी भी है। निजीकरण के बाद बैंकें सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि केवल निजी लाभ की खोज में रहेंगी। निजी बैंकों के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद, बैंकिंग सेवाएं बहुत

अधिक महंगी हो गई हैं। बहुत से लोगों के लिए जल्द ही ये सभी सेवाएं आर्थिक पोहच से बाहर हो जाएंगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सार्वजनिक धन का उपयोग करके और लाखों श्रमिकों के दशकों के परिश्रम से बनाया गया है। वे लोगों की संपत्ति हैं और उनका इस्तेमाल श्रमिकों, किसानों और अन्य सभी मेहनतकशों की जरूरतों को पूरा करने और उनके कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन, दसियों लाख करोड़ रुपये की भारी मात्रा में बड़े इजारेदार कंपनियों द्वारा लोगों के धन की ठगी की गई है और केंद्र सरकार इन्हें गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में घोषित कर देती है। उसी समय बैंकों के घाटे का पुनर्पूंजीकरण करने के लिए मेहनतकश लोगों पर कर के द्वारा उसका बोझ डाल देती है। ये वही बईमान पूंजीपति हैं जिन्हें सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सौंपना चाहती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के साथ, केंद्र सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के खिलाफ एक चौतरफा युद्ध की घोषणा की है जिसके तहत वे भारतीय लोगों के पैसों और मेहनत से बनी कीमती संपत्ति को भारतीय और विदेशी निजी इजारेदारों को सौंपना चाहती है। हम सबका संयुक्त संघर्ष ही सरकार को रोक सकता है।

साथ ही, हम सभी को हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के उपभोक्ताओं का समर्थन निजीकरण की नीतियों के खिलाफ की हमारी लड़ाई में जुटाना होगा। बैंकिंग सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के बीच, निजीकरण के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा कारने के आपके प्रयासों की हम सराहना करते हैं। एआईएफएपी के घटक भी अपने सदस्यों, परिवारों और लोगों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान करेंगे क्योंकि वे भी बैंक के ग्राहक हैं।

हम आपके "जनता के कल्याण के लिए जनता का धन" के नारे का और आपके संघर्ष का पूर्ण समर्थन करते हैं। एक पर हमला सभी पर हमला है!

एआईएफएपी अपने सभी घटक सदस्यों से बैंक कर्मियों के विभिन्न विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से समर्थन करने और इसमें भाग लेने का आग्रह करता है।

आपके समर्थन में,

सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फ़ोरम (AIFAP) के घटक (वर्णमाला क्रम में):

1. एयर इंडिया एम्पलोयीज यूनियन (AIEU),
2. एयर इंडिया सर्विस इंजीनियर्स एसिओसेशन (AISEA),
3. ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन (AICWF),
4. ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ एससी/एसटी और्गेनाइजेश्न्स (ऑल इंडिया परिसंघ)
5. ऑल इंडिया डिफेन्स एम्पलोयीज फेडरेशन (AIDEF),
6. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रीसिटी एम्पलोयीज (AIFEE),
7. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स (AIFOPDE),
8. ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल (AIGC),
9. ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA),
10. ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) एम्पलोयीज फेडरेशन,
11. ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन (AIPMA),
12. ऑल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (AIPDWF),
13. ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF),
14. ऑल इंडिया रेलवे एम्पलोयीज कॉन्फेडरेशन (AIREC) - पश्चिमी क्षेत्र,
15. ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (AIRF),
16. ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मैंटेनर्स यूनियन (AIRTU),
17. ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (AISMA),
18. ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर्स एसोसिएशन (AITCA),
19. भारत पेट्रोलियम टेक्नीकल और नौन- टेक्नीकल एम्पलोयीज एसोसिएशन (BPTNTEA) - मुंबई रिफाइनरी,
20. चित्तरंजन लोको वर्क्स (CLW) रेलवेमेन्स यूनियन, चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल,
21. चित्तरंजन रेलवेमेन्स कांग्रेस (CRMC), चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल,
22. कोचीन रिफाइनरी एम्पलोयीज एसोसिएशन (CREA-INTUC),
23. कन्टेनर कॉर्पोरेशन (CONCOR) एम्पलोयीज यूनियन,
24. डीएमडव्ल्यू रेलवे वर्कर्स यूनियन (DMWRWU), पटियाला, पंजाब,
25. दक्षिण रेलवे एम्पलोयीज यूनियन (DREU),
26. डीजल लोको आधुनिकीकरण वर्क्स (DMW) रेलवेमेन्स यूनियन, पटियाला, पंजाब,
27. डीजल लोको वर्क्स (DLW) मेन्स यूनियन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश,
28. इलेक्ट्रीसिटी एम्पलोयीज फेडरेशन ऑफ इंडिया (EEFI),
29. हिंदुस्तान पेट्रोलियम एम्पलोयीज यूनियन, विशाखापत्तनम रिफाइनरी,
30. हिंद खदान मजदूर फेडरेशन (HKMF),
31. इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री (ICF) लेबर यूनियन, चेन्नई, तमिलनाडु,
32. इंडियन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन (INWEF),
33. इंडियन रेलवे लोको रनिंगमेन ऑर्गनाइजेशन (IRLRO),
34. इंडियन रेलवे टिकटचेकिंग स्टाफ ऑर्गनाइजेशन (IRTCSO),
35. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मजदूर संघ (ICFMS), चेन्नई, तमिलनाडु,
36. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) लेबर यूनियन, चेन्नई, तमिलनाडु,

37.जोइंट एक्शन फ्रंट ऑफ पब्लिक सेक्टर ट्रेड यूनियन्स ऑफ बैंगलोर,
38.कामगार एकता कमिटी (KEC)/मजदूर एकता कमिटी (MEC)/तोयिलाली ओट्टूमइ इयक्कम (TOI),
39.लोक राज संगठन (LRS),
40.मध्य प्रदेश यूनाईटेड फ़ोरम ऑफ पावर एम्पलोयीज एंड इंजीनियर्स (MPUFPEE),
41.महाराष्ट्र स्टेट बैंक कर्मचारी संघ (MSBEF),
42.महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन (AITUC),
43.मेन्स कांग्रेस डीजल लोको वर्क्स (MCDLW) वाराणसी, उत्तर प्रदेश,
44.मुंबई एंड सबर्बन सेकंडरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन,
45.नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (NFIR),
46.नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलिकॉम एम्पलोयीज (NFTE)-BSNL,
47.नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम (NMOPS),
48.नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन (NRMU), मध्य रेलवे/कोंकण रेलवे,
49.नीलाचल एक्जिक्यूटिव्ज एसोसिएशन, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL),
50.पुरोगामी महिला संगठन (PMS),
51.रेल कोच फैक्ट्री मेन्स कांग्रेस (RCFMC), रायबरेली, उत्तर प्रदेश,
52.रेल कोच फैक्ट्री मजदूर यूनियन (RCFMU), कपूरथला, पंजाब,
53.रेल कोच फैक्ट्री (RCF) मेन्स यूनियन, कपूरथला, पंजाब,
54.रेल कोच फैक्ट्री (RCF) मेन्स यूनियन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश,
55.रेल व्हील फैक्ट्री कार्मिक संघ (RWFKS), बैंगलोर, कर्नाटक,
56.रेल व्हील फैक्ट्री (RWF) मजदूर यूनियन, बैंगलोर, कर्नाटक,
57.रिसर्च डिजाइन और स्टेंडर्ड ऑर्गनाइजेशन (RDSO) कर्मचारी संघ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश,
58.संचार निगम एक्जिक्यूटिव्ज एसोसिएशन (SNEA)-BSNL,
59.शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) ऑफिसर्स एसोसिएशन,
60.सूरत ट्रेड यूनियन कौंसिल (STUC),
61.टीचर्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, मुंबई,
62.अनऔरगेनाईज्ड वर्कर्स एंड एम्पलोयीज कॉग्रेस,
63.वैस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलोयीज यूनियन.